एक नजर में

अवकाश दिवसों में भी मंडी में नीलामी जारी रहेगी

खंडवा। किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति खंडवा में अवकाश दिवसों में भी फसलों की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी। मंडी बोर्ड भोपाल के निर्देशों के परिपालन में तथा व्यापारी संगठनों और कृषक संगठनों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

मंडी समिति के अनुसार 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च को अवकाश रहने के बावजूद खंडवा मंडी में समस्त कृषि जिंसों की नीलामी नियमित रूप से संचालित की जाएगी। मंडी प्रशासन ने सभी कृषक बंधुओं से आग्रह किया है कि वे उक्त तिथियों पर भी अपनी कृषि उपज विक्रय के लिए कृषि उपज मंडी खंडवा में लेकर आएं, ताकि उन्हें समय पर उचित मूल्य मिल सके।

इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

खंडवा। भूतड़ी अमावस्या और गुड़ी पड़वा के अवसर पर ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 17 मार्च सुबह 6 बजे से 19 मार्च रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत बुरहानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन देशगांव से खरगोन, कसरावद, खलघाट और महू होते हुए इंदौर की ओर जाएंगे। वहीं इंदौर से आने वाले भारी वाहन महू, खलघाट, कसरावद, खरगोन व भीकनगांव होते हुए देशगांव से खंडवा-बुरहानपुर मार्ग की ओर भेजे जाएंगे।

हालांकि दूध वाहन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, सेना, बिजली कंपनी, एलपीजी-पेट्रोलियम वाहन, सब्जी परिवहन वाहन तथा यात्री बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील की है।

त्यौहारों पर नर्मदा में नियमित जलप्रवाह रखने के निर्देश

खंडवा। भूतड़ी अमावस्या और गुड़ी पड़वा पर्व के अवसर पर ओंकारेश्वर, महेश्वर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने नर्मदा नदी में नियमित जलप्रवाह बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 17 से 19 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक नर्मदा नदी का जलस्तर स्थिर और समान बनाए रखा जाएगा, ताकि स्नान के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे।

इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि में अधिकतम तीन टरबाइन संचालित रखी जाएं। वहीं रात्रि के समय विद्युत मांग कम होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार तीन से कम टरबाइन भी चलाई जा सकेंगी, ताकि नदी का जलस्तर संतुलित बना रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

आयशर वाहन सहित 14 भैंसें जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

खंडवा। अवैध पशु परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंधाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आयशर वाहन से 14 भैंसें जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी पंधाना निरीक्षक दिलीप देवड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को 15-16 मार्च की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आयशर वाहन क्रमांक MP12ZF9855 में भैंसों को क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है।

सूचना पर उपनिरीक्षक सपन बाजपेई एवं टीम ने पंधाना-रुस्तमपुर रोड पर वाहन को रोककर जांच की। वाहन में 14 भैंसें ठूस-ठूस कर भरी मिलीं। पुलिस ने आरोपी जाहिद (32) निवासी खानशावली तथा सद्दाम (30) निवासी इमलीपुरा खंडवा को गिरफ्तार कर वाहन और भैंसें जब्त कीं। दोनों के खिलाफ पंधाना थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक

खंडवा। जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक मंगलवार को अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौडा की अध्यक्षता में जनपद पंचायत खंडवा के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिले की शासकीय व अशासकीय गौशालाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम जिले में उपलब्ध गौचर भूमि की स्थिति पर चर्चा की गई। अंजनी माता गौशाला, नंदमोहन गौशाला और श्रीराम गौशाला के प्रतिनिधियों ने चरनोई भूमि पर अतिक्रमण की समस्या रखी। इस पर अपर कलेक्टर श्रीमती गौडा ने संबंधित समस्याओं के 15 दिनों के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गौशालाओं को मृत पशुओं के शव निस्तारण के लिए समाधि खाद प्रक्रिया अपनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही गौशाला संचालकों से वर्षभर की आवश्यकता के अनुसार भूसा सुरक्षित रखने और किसानों से संपर्क कर भूसा दान के लिए प्रेरित करने को कहा। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. हेमंत शाह ने हिरण्य गर्भा योजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

बाल श्रम उन्मूलन पर संभागस्तरीय कार्यशाला

खंडवा। बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन तथा श्रम संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर इंदौर में संभागस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को उप श्रमायुक्त आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त मेघना भट्ट, सहायक श्रमायुक्त राखी जोशी, यूनिसेफ के राज्य सलाहकार विशेषज्ञ अमरजीत सिंह, सहायक श्रमायुक्त भानुप्रताप सिंह तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उपसंचालक पी.पी. पटेरिया ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, राज्य कार्ययोजना 2026-2030 तथा विभिन्न श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। संभागस्तरीय इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति खंडवा से अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, सदस्य मोहन मालवीय, स्वप्निल जैन, कविता पटेल तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई की शर्मिला मोरे भी शामिल रहीं। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन केवल श्रम विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, प्रशासन और न्याय तंत्र के समन्वित प्रयासों से ही बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को संवेदनशीलता और समन्वय के साथ कार्य करना होगा। कार्यशाला में विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने, बाल श्रम के मामलों में त्वरित कार्रवाई, प्रभावित बच्चों के पुनर्वास तथा संबंधित कानूनों के सख्ती से पालन पर विशेष जोर दिया गया।

घाटीखास की पहाड़ियों पर रचा इतिहास

कलेक्टर से लेकर विधायक तक ने उठाया फावड़ा

नवभारत न्यूज

खंडवा । जल संरक्षण की दिशा में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका खंडवा जिला एक बार फिर 'जल संचय जन भागीदारी 2.0' अभियान के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। पंधाना विकासखंड के ग्राम घाटीखास की पथरीली पहाड़ियों पर आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहाँ ग्रामीणजनों के साथ जिले के शीर्ष अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों ने चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर सामूहिक श्रमदान किया। इस भागीरथी प्रयास का मुख्य उद्देश्य गांव का पानी गांव में रोककर भूजल स्तर को पुनर्जीवित करना है।

पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में पन्धाना विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े, और खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव ने स्वयं फावड़ा चलाकर श्रमदान की शुरुआत की। प्रशासन की ओर से कलेक्टर ऋषव गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ नागार्जुन बी गौड़ा, सहायक कलेक्टर डॉ. कृष्णा सुशीर, और एसडीएम दिनेश सांवले सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

खंडवा को पुनः नंबर-1 बनाने का संकल्प : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक छाया मोरे ने रेखांकित किया कि पिछले वर्ष जल संरक्षण के क्षेत्र में खंडवा जिले ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने कहा, हमारी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है; इस वर्ष भी हम दोगुनी ऊर्जा के साथ कार्य कर खंडवा को देश के शिखर पर बनाए रखेंगे। वहीं, महापौर अमृता अमर यादव ने भारतीय संस्कृति में जल के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान 3.0' प्रारंभ हो रहा है, जिसके तहत शहर की एक-एक बूंद को सहेजने का संकल्प लिया गया है।

तकनीकी समाधान और भविष्य की योजना : कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पर्याप्त वर्षा के बावजूद ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट का मुख्य कारण वर्षा जल का प्रबंधन न होना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहाड़ियों पर गिरने वाला पानी तेजी से मिट्टी बहा ले जाता है, जिससे जमीन बंजर होती है। कंटूर ट्रेंच इन बूंदों की गति को रोककर उन्हें जमीन के भीतर समाने का अवसर देंगी।

जिला पंचायत सीईओ डॉ नागार्जुन बी गौड़ा ने बताया कि अकेले घाटीखास की पहाड़ियों पर 10 हजार कंटूर ट्रेंच निर्मित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, जिले भर की सड़कों के किनारों पर हजारों जल अवशोषक संरचनाएं बनाई जा रही हैं ताकि वर्षा का पानी व्यर्थ बहने के बजाय सीधे भूजल स्रोतों तक पहुँच सके।

एक साझा आह्वान : जिला पंचायत अध्यक्ष वानखेड़े ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन संरचनाओं के दूरगामी लाभों पर जोर दिया। अंत में, कलेक्टर ने मीडिया और नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान को एक जन-आंदोलन का रूप दें। 19 मार्च से शुरू होने वाले अभियान के तहत प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का सुरक्षित कोष तैयार किया जा सके।

राठौर समाज ने चुनाव में देरी को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार

खंडवा। राठौर सकल पंच समाज के वर्षों पुराने चुनावी विवाद में अब एक नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समाज के चुनाव 60 दिनों के भीतर संपन्न कराने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर हो रही देरी से समाज जनों में भारी असंतोष है। इसी सिलसिले में आज समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निवेदन किया। समाज के प्रतिनिधि और अधिवक्ता महेश कुमार राठौर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानूनी विवाद वर्ष 2009 में ट्रस्टियों की नियुक्ति के साथ शुरू हुआ था, जिसे लोक न्यास अधिकारी ने अवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय तक पहुँचा जहाँ लंबे समय तक स्थगन आदेश प्रभावी रहे। समाज का कहना है कि उन्होंने 16 फरवरी को ही आदेश की प्रमाणित प्रति लोक न्यास कार्यालय में जमा करवा दी थी, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी प्रशासन ने अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेश राठौर, अशोक राठौर, विजय राठौर, संजय राठौर और अमित राठौर, प्रीतम राठौर सहित समाज के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। समाज जनों ने प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष चुनाव के लिए लिखित सहमति दे चुके हैं, तो प्रशासन को अविलंब निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर प्रक्रिया को गति देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न नहीं कराए गए, तो समाज को मजबूरन न्यायालय की अवमानना की शरण लेनी पड़ेगी। अपर कलेक्टर ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।

नर्मदा के आंचल को मैला कर रहा गंदा नाला

श्रद्धालुओं की जान जोखिम में

ओंकारेश्वर। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में इन दिनों आस्था और अव्यवस्था के बीच एक भयावह तस्वीर उभर कर सामने आई है। जिस मां नर्मदा को मोक्षदायिनी मानकर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं, उसी पवित्र धारा में नगर का गंदा नाला जहर घोलने का काम कर रहा है। धर्मनगरी की सबसे बदतर स्थिति रामघाट के ऊपरी हिस्से में देखी जा रही है, जहाँ पूरे ओंकारेश्वर नगर की गंदगी और मल-मूत्र का नाला सीधे नर्मदा की मुख्य धारा में मिल रहा है। विडंबना यह है कि प्रशासन की इस घोर लापरवाही से अनभिज्ञ श्रद्धालु उसी दूषित पानी के बीच पवित्र मन से स्नान कर रहे हैं, जो न केवल उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य रोगों को भी खुला निमंत्रण दे रहा है।

गंदगी के इस आलम के बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव स्थिति को और भी चिंताजनक बना देता है। घाटों पर सुरक्षा के कोई पुख्ता संसाधन या रक्षा दल की तैनाती न होने के कारण यहाँ हर समय डूबने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन-प्रशासन और नगर परिषद किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। भूतड़ी अमावस्या और गुड़ी पड़वा को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने पुरजोर मांग की है कि खतरनाक और गंदे पानी वाले स्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए केवल चक्रसिद्ध घाट, चक्र तीर्थ घाट और गोमुख घाट जैसे स्वच्छ स्थानों पर तीनों पालियों में स्नान के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। नगर परिषद को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए तत्काल इन गंदे नालों का रुख मोड़ने की आवश्यकता है, ताकि नर्मदा का जल आचमन योग्य बना रहे। यदि समय रहते इन मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, तो न केवल तीर्थ की छवि धूमिल होगी, बल्कि श्रद्धालुओं का व्यवस्था से भरोसा भी उठ जाएगा।

ढेपड़ा परिवार ने श्रद्धांजलि सभा में समाज को सौंपे 1.51 लाख रुपये

खंडवा। मानवता की सच्ची सेवा वही है जो किसी की स्मृति को अमर बना दे। ग्राम कोरगला के प्रतिष्ठित ढेपड़ा परिवार ने इसी भावना को चरितार्थ करते हुए एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। स्वर्गीय गिरधारी लाल जी की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र दिलीप पटेल, त्रिलोक पटेल भाई रामकिशन ढेपड़ा एवं समस्त परिवार ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए कुल 1 लाख 51 हजार रुपये की सम्मान राशि अर्पित की है। परिवार ने गुर्जर समाज भवन कोरगला को 31 हजार रुपये और ओंकारेश्वर स्थित समाज की धर्मशाला के लिए 25 हजार रुपये की राशि भेंट की। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए ढेपड़ा परिवार ने शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में भी हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें छात्रवृत्ति अमर कोश, एक रोटी आश्रम और सनावद गौशाला सहित गणेश गौशाला में सहयोग राशि प्रदान की। इसके साथ ही शिव मंदिर, राम मंदिर कोरगला और गुर्जर समाज मांगलिक भवन सिलोदा में भी श्रद्धापूर्वक राशि भेंट की गई। इस गौरवपूर्ण अवसर पर समाज के अनेक प्रबुद्ध जन और वरिष्ठ पदाधिकारी साक्षी बने।

खाण्डववन की विरासत पर कागजी हरियाली का ग्रहण

विकास की बलि चढ़ते 1.24 लाख पेड़

नवभारत न्यूज

खंडवा। पौराणिक 'खाण्डववन' की गौरवशाली विरासत समेटे निमाड़ का अंचल आज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। वन विभाग के करोड़ों के बजट और हजारों कर्मचारियों की फौज के दावों के बीच धरातल पर केवल ठूंठ और अतिक्रमण का साम्राज्य नजर आ रहा है। विडंबना देखिए कि जिस जंगल को सहेजने की जिम्मेदारी विभाग की थी, वह आज अपनी ही विफलता के तीखे सवालों के घेरे में खड़ा है।

गिद्धों का सन्नाटा: पारिस्थितिक तंत्र की मौत की आहट : वन संरक्षण के खोखलेपन की पोल हालिया सर्वे ने खोल दी है। प्रकृति के 'सफाईकर्मी' कहे जाने वाले गिद्ध आज खंडवा के आसमान से पूरी तरह ओझल हो चुके हैं। सर्वे में एक भी गिद्ध का न मिलना इस बात का प्रमाण है कि जिले का पारिस्थितिक तंत्र ढह चुका है। विशेषज्ञ इसे एक 'साइलेंट डिजास्टर' मान रहे हैं। सवाल यह है कि करोड़ों के

संरक्षण बजट के बाद भी विभाग इन दुर्लभ पक्षियों के आवास और भोजन चक्र को बचाने में नाकाम क्यों रहा?

विकास या विनाश? 1.24 लाख पेड़ों पर चलेगी कुल्हाड़ी : एक ओर अवैध कटाई और अतिक्रमण जंगलों को निगल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महू-खंडवा

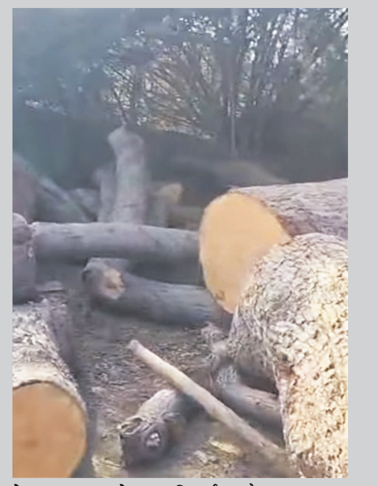

रेल लाइन गेज परिवर्तन के नाम पर सरकारी स्तर पर 1.24 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाने की तैयारी है। पर्यावरणविदों की चेतावनियों को दरकिनार कर दी गई यह अनुमति भविष्य में निमाड़ को 'तपती भट्टी' बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मार्च में ही अप्रैल- मई जैसी चिलचिलाती गर्मी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने प्रकृति के सुरक्षा कवच को बेरहमी से छिन्न-भिन्न कर दिया है।

अतिक्रमण और बढ़ता संघर्ष: फाइलों में सिमटी सख्ती : जिले के सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, लेकिन विभाग की कार्रवाई केवल छोटे-मोटे अभियान चलाकर सुर्खियां बटोरने तक सीमित है। इस प्रशासनिक ढुलमुलपन का भयावह परिणाम मानव-वन्यजीव संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। जब वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास उजाड़ दिए जाएंगे, तो वे रिहायशी इलाकों का रुख करेंगे ही। हालही में चांदगढ़ रेंज में तेंदुए की बढ़ती दहशत और ग्रामीणों का खौफ विभाग की दीर्घकालीन संरक्षण योजना की विफलता का जीवंत उदाहरण है।

बड़ी लापरवाही : नियमों को धुआं उड़ाती फैक्ट्रियां

भोजाखेड़ी देवझिरी मंदिर के समीप वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से एक फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। यह न केवल वन भूमि नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि दिन-रात उगलते धुएं से आसपास की आबोहवा जहरीली हो रही है। आखिर किसकी शह पर वन भूमि पर ये कारखाने चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन सैकड़ों टन बेशकीमती जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या विभाग को यह नजर नहीं आता या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं?

बहरहाल धूल के गुबार, बढ़ता प्रदूषण और चिलचिलाता तापमान आज खंडवा की नियति बन चुका है। यदि अब भी जिम्मेदार नहीं जागे, तो जिले में वनो का अस्तित्व केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएगा।